1	2	3
3. भंडारों में परिवर्तन	20662	12475
3.1 सरकारी क्षेत्र	5411	3015
3.2 निजी नेगमित क्षेत्र	4412	2270
3.3 घरेलू क्षेत्र	10839	7190
4. भूल-चूक	3880	980
5. भूल-चूक के लिए समायोजित सकल पूंजी निर्माण	145731	148715
6. बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	532030	615655

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता

5430. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने उत्तर प्रदेश में मकानों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थानों तथा राज्य स्तरीय उच्च आवास वित्त समितियों को पुनर्वित्त-पोषण सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसके द्वारा प्रदान की गई राशि का संस्थानवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा वितरित पात्र आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एसजीएचडी) में भी अभिदान करता है। पुनर्वित्त व्यक्तिगत हितग्राहियों को बड़ी मरम्मतों और उन्नयन के सहित आवास ऋणों के लिए और विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के संबंध में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि 1992-93 और 1993-94 (मार्च, 1994 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के संबंध में पुनर्वित्त का संवितरण क्रमशः 5730 लाख रुपए और 1683 लाख रुपए था।

देश में 1992-93 (जुलाई-जून) तथा 1993-94 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए संस्था-वार संवितरण निम्नलिखित थे :—

(करोड़ रुपए)

संस्थान	1992-93 (जुलाई-जून)	1993-94 (जुलाई-मार्च)
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	52.62	23.60
सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं	38.97	45.24
आवास वित्त कंपनियां	394.33	175.96
जोड़	485.92	244.80

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

Import Duty on Coal

5431. **SHRIMATI KAMLA SINHA**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the reduction in import duty on coal from 85% to 35% as proposed in the 1994-95 budget, will result in the dumping of imported coal in India at rates cheaper than that of domestic coal;

(b) whether such a reduction in import duty on coal will cause unnecessary expenditure of foreign exchange;

(c) whether Coal India Limited has the capacity to produce coal in sufficient quantities;